EDU TERIA
E - D.N.A
Daily Newspaper Analysis
Prelims Mains Essay
By: - Aarav Anand
Date: 11 Dec 2025
Source:- जनसत्ता

व्यापार वार्ता शुरू, अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीयर ने कहा

अमेरिका को भारत से अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव मिले

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 दिसंबर।

अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) जेमीसन ग्रीयर ने कहा है कि प्रस्तावित व्यापार समझौते पर भारत से 'अब तक के सबसे अच्छे' प्रस्ताव मिले हैं। यह बयान दोनों देशों के बीच दो-दिवसीय वार्ता शुरू होने के बीच आया है, जिसका उद्देश्य गहरे होते शुल्क गतिरोध को दूर करना है।

ग्रीयर ने वाशिंगटन में मंगलवार को सीनेट की विनियोग उपसमिति की सुनवाई में कहा कि भारत में कुछ 'रो क्राप्स' और अन्य मांस उत्पादों को लेकर प्रतिरोध है। अमेरिका में 'रो क्राप्स' की श्रेणी में मक्का, सोयाबीन, गेहूं और कपास को शामिल किया जाता है।

उन्होंने कहा कि ये एक कठिन मुद्दा रहा है... लेकिन वे काफी सकारात्मक रुख दिखा रहे हैं। जिस तरह के प्रस्ताव वे हमें दे रहे हैं, वे अब तक किसी भी देश से मिले सबसे बेहतर प्रस्ताव हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक व्यावहारिक वैकल्पिक बाजार हो सकता है।

ये टिप्पणियां महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि दोनों पक्ष प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण को अंतिम रूप देने की कोशिश में हैं। अमेरिकी दल व्यापार वार्ता के लिए इस समय भारत में है। दोनों देशों के बीच यहां शुरू हुई दो-दिवसीय वार्ता एक परस्पर लाभकारी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए हो रही है।

इन टिप्पणियों ने नई दिल्ली में चल रही महत्त्वपूर्ण चर्चाओं के लिए एक रचनात्मक पृष्ठभूमि तैयार की है। वार्ता के पहले दिन वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने अमेरिका के उप व्यापार प्रतिनिधि रिक स्विट्जर से मुलाकात की। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने भारत-अमेरिका व्यापार एवं आर्थिक संबंधों से जुड़े मामलों पर विचार-विमर्श किया। इसमें एक पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत भी शामिल है।

यह वार्ता 11 दिसंबर को खत्म होगी। यह बातचीत इस लिहाज से अहम है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी बाजारों में प्रवेश करने वाले भारतीय उत्पादों पर अगस्त से ही 50 फीसद का भारी शुल्क लगा दिया है। इसके बाद द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर जारी बातचीत भी पटरी से उतर गई।

हालांकि शीर्ष नेतृत्व की पहल से यह फिर से शुरू हो गई, लेकिन अभी तक समझौते के शुरुआती चरण को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। भारतीय उद्योग और निर्यातक इस बातचीत के नतीजों और किसी समझौते की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऊंचे आयात शुल्क अमेरिका को होने वाले उनके निर्यात को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

विदेश सचिव विक्रम मिसरी और अमेरिकी उप व्यापार प्रतिनिधि रिक स्विटजर बुधवार को नई दिल्ली में।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीयर

यह बयान दोनों देशों के बीच दो-दिवसीय वार्ता शुरू होने के बीच आया है, जिसका उद्देश्य गहरे होते शुल्क गतिरोध को दूर करना है।
ये टिप्पणियां महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि दोनों पक्ष प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण को अंतिम रूप देने की कोशिश में हैं। अमेरिकी दल व्यापार वार्ता के लिए इस समय भारत में है।

पौष्टिक आहार का गहराता संकट

भारत में भोजन और पोषण का संकट दो ध्रुवों में बंटा दिखता है। ग्रामीण भारत में अब भी कुपोषण, रक्ताल्पता, कम वजन जैसे मामलों का उच्च स्तर पाया जाता है। यहां बच्चों और महिलाओं की पोषण स्थिति विशेष चिंता का विषय है। दूसरी ओर, शहरी क्षेत्र में भोजन की उपलब्धता तो है, पर उसकी गुणवत्ता की समस्या है।

मनीष जैसल

दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां आर्थिक तरक्की और तकनीक की चमक के बीच भोजन जैसी बुनियादी जरूरत इंसान की पहुंच से दूर होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रपट बताती है कि दुनिया की बयालीस फीसद आबादी पौष्टिक भोजन पर खर्च नहीं कर पाती। यह केवल गरीबी का आंकड़ा नहीं, बल्कि वैश्विक नीतियों, बाजार व्यवस्थाओं और आर्थिक असमानताओं का ऐसा आईना है, जिसमें हमारी सामूहिक विफलता दिखती है। जब भोजन जैसे मानव अधिकार को भी बाजार के हवाले कर दिया जाए, तो समाज कमजोर होता है, चाहे वह कितना ही विकसित क्यों न दिखे। भारत का विकास ढांचा मजबूत दिख सकता है, पर उसकी बुनियाद में पोषण का अभाव साफ महसूस होता है।

वैश्विक स्तर पर देखें तो अफ्रीका, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देश पौष्टिक भोजन के संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सहारा के दक्षिण वाले अफ्रीकी क्षेत्र में तो हालात इतने खराब हैं कि 60 से 80 फीसद आबादी पौष्टिक भोजन का खर्च ही नहीं उठा सकती। वहीं यूरोप, आस्ट्रेलिया और उत्तर अमेरिका जैसे क्षेत्रों में भोजन की पहुंच बेहतर है, पर वहां असंतुलित आहार, प्रसंस्कृत खाद्य और मोटापे जैसी समस्याएं स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रही हैं। भारत में भोजन और पोषण का संकट दो ध्रुवों में बंटा दिखता है। ग्रामीण भारत में अब भी कुपोषण, रक्ताल्पता, कम वजन जैसे मामलों का उच्च स्तर पाया जाता है। बच्चों और महिलाओं की पोषण स्थिति विशेष चिंता का विषय है। दूसरी ओर, शहरी भारत में खाने की उपलब्धता तो है, पर उसकी गुणवत्ता की समस्या है। समय की कमी, काम का तनाव, और तेज बाजार-चालित संस्कृति ने डिब्बाबंद खाद्य, जंक फूड और मीठे पेयों को रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा बना दिया है। एक तरफ कुपोषण और दूसरी ओर अतिपोषण, दोनों मिलकर स्वास्थ्य संकट को और जटिल बनाते हैं।

खाद्य महंगाई ने भारतीय रसोई को जिस तरह प्रभावित किया है, वह चिंता का विषय है। दालें, खाद्य तेल, फल, सब्जियां और दूध जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने संतुलित भोजन की लागत बहुत बढ़ा दी है। एक औसत भारतीय परिवार की मासिक आमदनी का बड़ा हिस्सा केवल कैलोरी-आधारित भोजन पूरा करने में ही खर्च हो जाता है, जबकि पौष्टिक भोजन की थाली उनकी पहुंच से दूर चली जाती है। यह स्थिति बताती है कि भोजन केवल बाजार व्यवस्था का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एक सामाजिक सुरक्षा अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत की कृषि अब भी मानसून पर अत्यधिक निर्भर है। मगर असामान्य बारिश, सूखा, बाढ़ और तापमान में बदलाव ने फसल उत्पादकता को प्रभावित किया है, जिससे बाजार में दाम बढ़ते हैं। समस्या नीतिगत प्राथमिकताओं की है। भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली अभी भी मुख्य रूप से अनाज-आधारित है, गेहूं और चावल पर केंद्रित है। जबकि शरीर को विविध पोषक तत्त्वों की भी आवश्यकता होती है।

भारत में फल, सब्जियां, दालें, अंडे और डेयरी जैसे घटक बड़े पैमाने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली या सरकारी पोषण कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। इसी वजह से मध्याह्न भोजन की तरह अन्य योजनाएं भोजन तो देती हैं, पर पूर्ण पोषण सुनिश्चित नहीं कर पातीं। दुनिया के कई देशों ने भोजन को राष्ट्रीय

विकास की धुरी बनाकर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। ब्राजील का 'शून्य भुखमरी' अभियान इसका उदाहरण है, जिसने स्थानीय कृषि, सब्सिडी और पोषण कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया। जापान ने 'शोकू इकु' नीति के तहत बच्चों को भोजन विज्ञान की शिक्षा दी। एक ऐसा ढांचा, जो स्पष्ट करता है कि भोजन केवल खाने की वस्तु नहीं, बल्कि संस्कृति, समझ और स्वास्थ्य का आधार है। दक्षिण कोरिया ने प्रसंस्कृत खाद्य पर सख्त नियंत्रण लागू किए, जिससे जीवनशैली संबंधी बीमारियों में गिरावट आई। भारत इनसे सीख लेकर अपने कार्यक्रमों को अधिक वैज्ञानिक और आधुनिक बना सकता है। दरअसल, पोषण की कमी का असर व्यक्तिगत स्तर से कहीं अधिक व्यापक है। यह कार्यक्षमता, शिक्षा और उत्पादकता को प्रभावित करता है। कमजोर और कुपोषित बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। कुपोषित युवा समाज में सक्रिय योगदान देने में पीछे रह जाते हैं।

> **खाद्य महंगाई ने भारतीय रसोई को जिस तरह प्रभावित किया है, वह चिंता का विषय है। दालें, खाद्य तेल, फल, सब्जियां और दूध जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने संतुलित भोजन की लागत बहुत बढ़ा दी है। एक औसत भारतीय परिवार की मासिक आमदनी का बड़ा हिस्सा केवल कैलोरी-आधारित भोजन पूरा करने में ही खर्च हो जाता है, जबकि पौष्टिक भोजन की थाली उनकी पहुंच से दूर चली जाती है। यह स्थिति बताती है कि भोजन केवल बाजार व्यवस्था का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एक सामाजिक सुरक्षा अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए।**

यह समझना आवश्यक है कि भोजन कोई साधारण आर्थिक वस्तु नहीं है। यह सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकार का मूल तत्त्व है। जब एक बड़ी आबादी पौष्टिक भोजन वहन नहीं कर पाती, तो समाज के लिए यह अनदेखा करने योग्य आंकड़ा नहीं रह जाता। यह वह बिंदु है, जहां नीतियों, बाजार, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य-चारों को मिलकर समाधान तैयार करना होगा। भारत के पोषण संकट को समझने के लिए एक स्वस्थ थाली में वास्तव में क्या होना चाहिए, यह समझने की जरूरत है। बच्चों की थाली में प्रोटीन (दाल, अंडा, दूध), कैल्शियम, आयरन, हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा अनिवार्य हैं। ये तत्त्व न केवल हड्डियों और दिमाग के विकास के लिए जरूरी हैं, बल्कि रक्ताल्पता, संक्रमणों की अधिकता, थकान, आंखों की कमजोरी और सीखने की क्षमता में कमी जैसी समस्याओं से भी बचाते हैं। यह अफसोसनाक है कि भारत के लाखों बच्चों की थाली आज भी इन आवश्यक तत्त्वों से खाली है और इसका असर उनके पूरे जीवन पर पड़ता है।

महिलाओं और वृद्धों के पोषण की जरूरतें इससे भी अधिक विशिष्ट हैं। महिलाओं को विशेष रूप से आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन की अधिक मात्रा चाहिए। वहीं वृद्धजन के लिए ओमेगा-3, फाइबर, विटामिन बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम अत्यंत आवश्यक हैं, जो उन्हें हृदय रोग, मधुमेह, हड्डियों के क्षरण और पाचन संबंधी समस्याओं से बचाते हैं। लेकिन पारिवारिक और सामाजिक संरचना के कारण अक्सर इन्हीं समूहों की थाली सबसे पहले कमजोर होती है, जिससे बीमारी एक स्थायी साथी बन जाती है। सरकारी नीतियां और जमीनी ढांचा पोषण सुधार का दूसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं। देश में आंगनबाड़ी और स्कूल का भोजन कक्ष बच्चों के पोषण का बड़ा आधार माने जाते हैं, पर इनकी स्थिति असमान और अक्सर संसाधन-विहीन नजर आती है। आज भारत के सामने प्रश्न यह नहीं कि भोजन कितनी मात्रा में उपलब्ध है, बल्कि यह है कि क्या गुणवत्ता पूरक भोजन सही कीमत और सही समय पर हर नागरिक तक पहुंच पा रहा है?

भारतीय कृषि में कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग जिस तेजी से बढ़ा है, वह पोषण संकट का एक और अदृश्य कारण बन रहा है। खेतों में सब्जियों और फलों पर अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों का छिड़काव न केवल फसलों की गुणवत्ता को कम करता है, बल्कि लंबे समय में लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर दुष्प्रभाव छोड़ता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि इन रसायनों का अंश खाद्य पदार्थों में बचा रह जाता है, जिससे बच्चों में तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं, महिलाओं में हार्मोन असंतुलन और वयस्कों में कैंसर और गुर्दा रोगों का खतरा बढ़ जाता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस क्षेत्र में न तो निगरानी सख्त है, न ही किसानों को सुरक्षित विकल्पों की पर्याप्त जानकारी मिल पाती है। जैविक खेती और कम-रसायन जैसे विकल्पों की चर्चा तो होती है, पर जमीनी स्तर पर उनकी पहुंच नगण्य है। अगर राष्ट्र एक मजबूत, सक्षम और स्वस्थ भविष्य चाहता है, तो भोजन को बाजार का उत्पाद नहीं, बल्कि सार्वभौमिक अधिकार घोषित करना होगा। तभी वास्तविक विकास की नींव मजबूत होगी।

दस फीसद की कटौती के बाद इंडिगो की 220 उड़ानें रद्द

डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को तलब किया, हवाई अड्डों के हालात पर नजर रखेगी आठ सदस्यीय टीम

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 दिसंबर।

इंडिगो एअरलाइंस ने बुधवार को दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु समेत प्रमुख हवाई अड्डों पर करीब 220 उड़ानें रद्द कर दीं। सरकार ने एक दिन पहले ही इंडिगो के शीतकालीन उड़ान कार्यक्रम में दस फीसद की कटौती कर दी है।

विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने संकटग्रस्त इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स को गुरुवार को उनके कार्यालय में उपस्थित होने और हालिया परिचालन व्यवधानों से संबंधित व्यापक एवं अद्यतन जानकारी से लैस एक रपट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। नियामक के आदेशानुसार, विमानन कंपनी को उड़ानें बहाल करने, पायलटों तथा चालक दल की भर्ती योजना, पायलट व चालक दल की अद्यतन संख्या, रद्द की गई उड़ानों की संख्या और 'रिफंड' आदि से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। मौजूदा संकट के बीच यात्रियों की सहूलियत के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए)ने आठ सदस्यीय निगरानी टीम गठित की है जो लगातार प्रमुख हवाई अड्डों समेत एअरलाइन के मुख्यालय पर हालात पर लगातार नजर रखेगी। एक दिसंबर से जारी इंडिगो संकट के कारण देश के तमाम हवाई अड्डों पर यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विमानन मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद हालात में लगातार सुधार जारी हैं। मंत्रालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा या नियमों की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी भी गठित कर दी गई है। इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीइओ) पीटर एल्बर्स ने दावा किया था कि एअरलाइन का परिचालन दोबारा पटरी पर आ गया है। लाखों ग्राहकों को उनके टिकट का पूरा शुल्क लौटाया जा चुका है। हालांकि, अचानक रद्द, बहुत देरी या बगैर सहमति के पुनर्निर्धारित की गई उड़ानों के यात्रियों के मुआवजे पर एल्बर्स ने चुप्पी साधे रखी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के यात्रियों के नियम के मुताबिक, अगर कोई विमानन कंपनी प्रस्थान से कम से कम दो हफ्ते पहले यात्री को उसकी उड़ान रद्द होने की सूचना देने में विफल रहती है, तो मुआवजा देना कानूनी रूप से अनिवार्य है और इसकी राशि उड़ान की अवधि पर निर्भर करती है।

टीम के सदस्य परिचालन मानकों की रोजाना भेजेंगे रपट

गंभीर संकट से उबर रही इंडिगो मुख्यालय पर टीम के दो सदस्यों को तैनात किया जाएगा जो रोजाना परिचालन मानकों के पालन से संबंधित रपट डीजीसीए को भेजेंगे। टीम के सदस्य उड़ानों के रद्द होने, चालक दल की कमी के कारण समस्या, पायलटों की संख्या, टिकट की रकम वापसी और प्रभावित यात्रियों के मुआवजे सहित एअरलाइन के आवागमन के समय और रुकावट के दौरान फंसे यात्रियों के सामान वापसी पर भी नजर रखेगी। विमानन नियामक ने अपने अधिकारियों को 11 हवाई अड्डों का तत्काल निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं। इनमें जयपुर, नागपुर, सूरत, भोपाल, तिरुपति, शिरड़ी, लखनऊ, अमृतसर, देहरादून के अलावा दूसरे शहर भी शामिल हैं।

इंडिगो ने नियामक को सौंपी संशोधित समय-सारिणी

इंडिगो ने हजारों उड़ानें रद्द होने के बाद उसकी उड़ानों की संख्या में 10 फीसद की कटौती के बाद अपनी संशोधित शीतकालीन समय-सारिणी विमानन नियामक को सौंप दी है। एअरलाइन को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बुधवार शाम पांच बजे तक संशोधित समय-सारिणी जमा करने का निर्देश दिया था। इंडिगो चालक दल की कमी के कारण सेवाओं में व्यवधान को लेकर डीजीसीए की कड़ी निगरानी में है। इंडिगो ने मंगलवार के आदेश के मुताबिक संशोधित शीतकालीन समय-सारिणी, विमानन नियामक को सौंप दी है। हालांकि योजना के तहत इंडिगो ने किन मार्गों पर उड़ानें कम करने पर सहमति दी है, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने मंगलवार को कहा था कि 10 फीसद कटौती का उद्देश्य इंडिगो की समय-सारिणी को एअरलाइन में उपलब्ध पायलटों के अनुरूप बनाना है।

'जांच में बाहरी विशेषज्ञ भी किए जाएंगे शामिल'

इंडिगो संकट को लेकर विमानन कंपनी के अध्यक्ष विक्रम सिंह मेहता ने माफी मांगते हुए कहा, कंपनी इस संकट की पूरी जिम्मेदारी लेती है। तीन दिसंबर को हुई अप्रत्याशित घटनाओं की शृंखला की वजह से उड़ानों का परिचालन प्रभावित होने से यात्रियों को हुई असुविधा खेद जताया। संकट के कारणों की जांच में कंपनी के अंदरूनी तंत्र के अलावा बाहरी विशेषज्ञों को भी शामिल करने का इंडिगो बोर्ड ने निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य संकट के कारणों का पता लगाने सहित परिचालन के प्रभावित होने के कारणों की जांच की जाएगी। यह जानना जरूरी है कि गलती कहां हुई, ऐसी स्थिति दोबारा न हो। वहीं दूसरी ओर माकपा सदस्य एए रहीम ने बुधवार को राज्यसभा में इंडिगो संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह संकट केवल इंडिगो का नहीं है। इस पूरे बड़े संकट के लिए एकमात्र दोषी केंद्र सरकार है।

प्रश्न – वर्तमान में उत्पन्न इंडिगो एयरलाइन्स से संबंधित समस्याओं को रेखांकित करें तथा इसके निदान के लिए सरकार के प्रयासो का समालोचनात्मक व्याख्या करें।

38 Marks

अमेजन 2030 तक भारत में 35 अरब डालर का करेगा निवेश

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा)।

अमेरिकी ई-कामर्स कंपनी अमेजन ने भारत में 2030 तक अपने सभी व्यवसायों में 35 अरब अमेरिकी डालर का भारी निवेश करने की योजना की बुधवार को घोषणा की।

कंपनी का मकसद कृत्रिम मेधा (एआइ) संचालित डिजिटलीकरण, निर्यात वृद्धि और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करना है। अमेजन ने यह घोषणा माइक्रोसाफ्ट द्वारा भारत में 2030 तक डेटा सेंटर, एआइ और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 17.5 अरब अमेरिकी डालर के निवेश की प्रतिज्ञा जताने के एक दिन की है। इससे पहले गूगल ने अगले पांच वर्षों में एआइ डेटा सेंटर बनाने के लिए 15 अरब अमेरिकी डालर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई थी। अमेजन ने कहा कि 2030 तक कृत्रिम मेधा और लाजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में उसके निवेश से भारत में अतिरिक्त 10 करोड़ नौकरियां उत्पन्न करने में मदद मिलेगी। ई-कामर्स कंपनी अमेजन..वालमार्ट समर्थित फ्लिप कार्ट के साथ-साथ अरबपति मुकेश अंबानी की घरेलू कंपनियों और इटर्नल लिमिटेड की ब्लिंक्ट, स्विगी लिमिटेड की इंस्टामार्ट एवं जेप्टो जैसी तुरंत 'डिलीवरी' करने वाली कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए निवेश बढ़ा रही है। अमेजन ने 2010 से भारत में 40 अरब अमेरिकी डालर का निवेश किया है।

निवेश से भारत में अतिरिक्त 10 करोड़ नौकरियां उत्पन्न करने में मदद मिलेगी।

शोध

ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद के अध्ययन से सामने आई जानकारी

अमीर आबादी सबसे गरीब की तुलना में 1.5 गुना अधिक प्रोटीन लेती है

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 दिसंबर।

भारतीयों के खाने में प्रोटीन की मात्रा का लगभग आधा हिस्सा अब चावल, गेहूं, सूजी और मैदा जैसे अनाजों से आता है। भारत की सबसे अमीर 10 फीसद आबादी सबसे गरीब आबादी की तुलना में अपने घर पर 1.5 गुना अधिक प्रोटीन का सेवन करती है, और पशु-आधारित प्रोटीन के स्रोतों तक उसकी पहुंच भी अधिक है।

यह जानकारी ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद (सीईईडब्लू) के एक नए स्वतंत्र अध्ययन से सामने आई है। इसमें 2023-24 एनएसएसओ घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर खान-पान के रुझानों का विश्लेषण किया गया है। भारतीय औसतन 55.6 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन का सेवन करते हैं, लेकिन इस अध्ययन में पाया गया है कि इस प्रोटीन का लगभग 50 फीसद हिस्सा अनाजों से आता है, जिनमें कम गुणवत्ता वाला 'अमीनो एसिड' होता है। वे आसानी से पचते नहीं हैं। प्रोटीन में अनाजों की यह हिस्सेदारी राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआइएल) की ओर से सुझाई गई 32 फीसद की मात्रा से बहुत अधिक है। दालें, डेयरी उत्पाद और अंडे/मछली/मांस जैसे उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन के स्रोत भोजन से बाहर जा रहे हैं। प्रोटीन शारीरिक विकास, सुधार और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करता है। सीईईडब्लू अध्ययन में यह भी पाया है कि भोजन में सब्जी, फल और दाल जैसे प्रमुख खाद्य समूहों का सेवन कम है, जबकि खाना पकाने के तेल, नमक और चीनी की अधिकता है।

भारतीय औसतन 55.6 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन का सेवन करते हैं, लेकिन इस अध्ययन में पाया गया है कि इस प्रोटीन का लगभग 50 फीसद हिस्सा अनाजों से आता है, जिनमें कम गुणवत्ता वाला 'अमीनो एसिड' होता है। वे आसानी से पचते नहीं हैं।

सीईईडब्लू के फेलो अपूर्व खंडेलवाल ने कहा कि यह अध्ययन भारत की खाद्य प्रणाली में एक छिपे हुए संकट को सामने लाता है, जैसे कम गुणवत्ता के प्रोटीन पर बहुत अधिक निर्भरता, अनाजों व तेलों से अतिरिक्त कैलोरी का सेवन, विविधतापूर्ण व पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य सामग्री का बहुत कम उपयोग। सबसे गरीब 10 फीसद घरों का एक व्यक्ति एक सप्ताह में केवल दो-तीन गिलास दूध और दो केले के बराबर फल खाता है, जबकि सबसे अमीर 10 फीसद घरों का एक व्यक्ति आठ-नौ गिलास दूध और आठ-दस केले के बराबर फल खाता है। खान-पान का यह अंतर संतुलित आहार तक पहुंच में व्यापक असमानता दर्शाता है। इसी के साथ पोषण और आय के लिए सिर्फ कुछ फसलों पर अत्यधिक निर्भरता इसका जलवायु अनुकूलन घटा देती है। इसलिए खाने की थाली से लेकर खेत तक विविधता लाना, एक राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। एक दशक में भारत का प्रोटीन सेवन थोड़ा बढ़ा है, लेकिन यह पर्याप्त है। भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत प्रोटीन सेवन 2011-12 और 2023-24 के बीच 60.7 ग्राम से बढ़कर 61.8 ग्राम और शहरी क्षेत्रों में 60.3 ग्राम से बढ़कर 63.4 ग्राम हो गया है।

सीईईडब्लू के विश्लेषण से पता चलता है कि इन औसत के पीछे गहरी असमानता मौजूद है। भारत की सबसे अमीर 10 फीसद आबादी सबसे गरीब आबादी की तुलना में अपने घर पर 1.5 गुना अधिक प्रोटीन का सेवन करती है और पशु-आधारित प्रोटीन के स्रोतों तक उसकी पहुंच भी अधिक है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर किया दावा, बोले

पाकिस्तान और भारत के युद्ध को मैंने खत्म करवाया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 दिसंबर।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दावे को फिर से दोहराते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान में 'जंग छिड़ी हुई थी' और उन्होंने ही परमाणु हथियारों से लैस दोनों पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष को समाप्त कराया। ट्रंप अब तक लगभग 70 बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को रुकवाया था।

ट्रंप ने मंगलवार को पेंसिल्वेनिया के माउंट पोकोनो में अर्थव्यवस्था पर एक रैली में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि दस महीनों में मैंने आठ युद्ध समाप्त करवाए जिनमें कोसोवो (और) सर्बिया, पाकिस्तान और

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कंबोडिया और थाईलैंड में फिर से लड़ाई शुरू हो गई है और वह उन देशों को फोन करेंगे।

भारत, इजराइल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया, आर्मेनिया और अजरबैजान शामिल हैं, वे आपस में लड़ रहे थे। भारत ने छह और सात मई की रात को आपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया था। पहलगाम आतंकी हमले में 26 नागरिक मारे गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार से ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद संघर्ष समाप्त करने के लिए 10 मई को सहमति बनी। भारत ने संघर्ष के समाधान में किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से लगातार इनकार किया है।

इसी बीच, ट्रंप ने कहा कि कंबोडिया और थाईलैंड में फिर से लड़ाई शुरू हो गई है और वह उन देशों को फोन करेंगे। ऐसा कौन कह सकता है कि मैं एक फोन काल करके थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों के बीच जारी युद्ध को रोक दूंगा? वे आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन मैं यह करूंगा। इसलिए हम ताकत के बल पर शांति स्थापित कर रहे हैं। हम यही कर रहे हैं।

'द लैंसेट' में प्रकाशित रपट से खुलासा | चिंताजनक | उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में हालत ज्यादा खराब

एक अरब लड़कियों ने झेली यौन हिंसा, इनमें 23 फीसद भारत की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 दिसंबर।

'द लैंसेट' पत्रिका में प्रकाशित अनुमानों के अनुसार 2023 में दुनिया भर में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की एक अरब से अधिक महिलाओं ने बचपन में यौन हिंसा झेली और लगभग 60.8 करोड़ महिलाएं अंतरंग साथी द्वारा की गई हिंसा की शिकार रहीं। उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में अंतरंग साथी द्वारा की गई हिंसा और यौन हिंसा दोनों की सबसे अधिक दर पाई गई।

शोधकर्ताओं ने कहा कि इन क्षेत्रों में हिंसा से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव एचआइवी और अन्य दीर्घकालिक बीमारियों की उच्च दर के कारण और भी गंभीर हो जाते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार भारत में अंतरंग साथी द्वारा की गई हिंसा की शिकार महिलाओं की दर 23 फीसद रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अनुमान है कि 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग की 30 फीसद से अधिक महिलाओं और लगभग 13 फीसद पुरुषों ने बचपन में यौन हिंसा झेली।

शोधकर्ताओं ने 'ग्लोबल बर्डन आफ डिजीज' (जीबीडी) शोध 2023 के आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिसे विभिन्न क्षेत्रों और समय के आधार पर स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान को मापने का अब तक का सबसे बड़ा और व्यापक प्रयास माना जाता है। इस जीबीडी अध्ययन का समन्वय अमेरिका की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने किया था।

लेखकों ने शोध में लिखा, 'विश्व स्तर पर, हमने अनुमान लगाया कि 2023 तक 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की 60.8 करोड़ महिलाएं कभी न कभी अंतरंग साथी द्वारा हिंसा का शिकार हुई हैं, और 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के 1.01 अरब व्यक्तियों ने बचपन में यौन हिंसा का अनुभव किया।'

वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने नवंबर में प्रकाशित एक वैश्विक रपट में अनुमान लगाया था कि 2023 में भारत में 15-49 वर्ष की आयु की महिलाओं का 1/5 से ज्यादा हिस्सा इअंतरंग साथी की हिंसा का शिकार हुआ जबकि लगभग 30 फीसद को उनके जीवनकाल में कभी न कभी ऐसी हिंसा का शिकार होना पड़ा।

दुनियाभर में लगभग तीन में से एक या 840 मिलियन ने अपने जीवनकाल में साथी या यौन हिंसा का सामना किया।

घरेलु हिंसा और यौन हिंसा बीमारी के बोझ

शोधकर्ताओं ने कहा, 'कमजोर स्वास्थ्य प्रणालियों और महिलाओं और बच्चों के लिए सीमित कानूनी सुरक्षा वाले क्षेत्रों को इन नुकसानों को संबोधित करने और रोकने में और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।' जबकि उच्च आय वाले देशों में कुल मिलाकर प्रसार दर कम होती है, फिर भी उन्हें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें घरेलु और यौन हिंसा बीमारी के बोझ के लिए शीर्ष जोखिम कारकों में से हैं, खासकर 15-49 वर्ष की आयु के युवा वयस्कों में।

मानसिक स्थिति पर बुरा असर

विश्व स्तर पर, बचपन में यौन हिंसा का शिकार हुई 15 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं की संख्या दस लाख से भी ज्यादा है। वहीं, 15 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं की अनुमानित संख्या 608 मिलियन है, जिन्होंने घरेलू हिंसा का भी अनुभव किया है। आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली, गोरखपुर और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़, आइसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट फार रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस, चेन्नई के लेखकों वाली इस रपट में बताया गया है कि ये अनुभव लंबे समय तक चलने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े हैं। इनमें अवसाद और चिंता, पुरानी बीमारियां और समय से पहले मौत का बढ़ा हुआ खतरा शामिल है।

कर्नाटक विस में घृणास्पद भाषण व घृणा अपराध रोकथाम विधेयक पेश

एक लाख रुपए जुर्माना और दस साल कैद का प्रावधान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 दिसंबर।

कर्नाटक सरकार ने बुधवार को राज्य विधानसभा में भाजपा के विरोध के बीच कर्नाटक घृणास्पद भाषण और घृणा अपराध (रोकथाम) विधेयक पेश किया जिसमें एक लाख रुपए तक के जुर्माने और 10 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने चार दिसंबर को इस विधेयक को मंजूरी दी थी।

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया। विधेयक के अनुसार, किसी भी प्रकार का ऐसा व्यक्तव्य- चाहे वह बोले गए शब्दों के माध्यम से हो, लिखित रूप में हो, इशारों या दृश्यमान प्रतीकों द्वारा हो, इलेक्ट्रानिक संचार के माध्यम से हो या किसी अन्य तरीके से-जो सार्वजनिक रूप से किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी वर्ग, समूह या समुदाय के प्रति चोट पहुंचाने, असहमति, शत्रुता, द्वेष या बुरे इरादे से किया गया हो और किसी पक्षपाती हित की पूर्ति के उद्देश्य से हो, उसे घृणास्पद भाषण माना जाएगा। धर्म, जाति, नस्ल या समुदाय, लिंग, लैंगिक पहचान, यौन अभिविन्यास, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, दिव्यांगता या जनजाति के आधार पर किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह भी घृणास्पद भाषण की श्रेणी में रखा गया है।

परमेश्वर ने सदन में विधेयक पेश करने की अनुमति मांगी और अध्यक्ष यू टी खादर ने इसे ध्वनि मत के लिए रखा, तो विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने 'नहीं' के नारे लगाकर इसका विरोध किया। हालांकि, सुनील कुमार जैसे कुछ भाजपा सदस्यों ने मत विभाजन की मांग की, फिर भी अध्यक्ष ने सदन में विधेयक पेश करने की प्रक्रिया जारी रखी। विधानसभा में विधेयक पेश होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि निश्चित रूप से घृणास्पद भाषण (रोकथाम) सरकार के एजंडे का हिस्सा है। आप घृणास्पद भाषण को होने नहीं दे सकते। हमें राज्य में शांति, कानून-व्यवस्था बनाए रखनी है।

पूर्वाग्रह आधारित हित का अर्थ है और इसमें धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, लैंगिक पहचान, यौन अभिविन्यास, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, दिव्यांगता या जनजाति के आधार पर पूर्वाग्रह शामिल हैं। 'घृणा अपराध' को घृणास्पद भाषण के संचार के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें इसे तैयार करना, प्रकाशित करना या प्रसारित करना शामिल है। घृणास्पद भाषण का संचार ऐसी अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो सार्वजनिक रूप से मौखिक, मुद्रित, प्रकाशन, इलेक्ट्रानिक माध्यमों या अन्य साधनों के माध्यम से ऐसे घृणास्पद भाषण को व्यक्त करती हो।

जूनियर पुरुष विश्व कप

भारत ने अर्जेंटीना को हराकर नौ साल बाद कांस्य पदक जीता

चेन्नई, 10 दिसंबर (भाषा)।

आखिरी 11 मिनट में चार गोल करके भारत ने 2021 की चैंपियन अर्जेंटीना को बुधवार को कांस्य पदक के प्लेआफ मुकाबले में 4-2 से हराकर नौ साल बाद जूनियर पुरुष हाकी विश्व कप में पदक जीत लिया। दो बार (होबार्ट 2001 और लखनऊ 2016) में चैंपियन रही भारतीय टीम ने आखिरी बार नौ साल पहले कोई पदक जीता था। पिछले दो बार टीम कांस्य पदक का मुकाबला हारकर चौथे स्थान पर रही थी।

भारत के लिए अंकित पाल (49वां), मनमीत सिंह (52वां), शारदानंद तिवारी (57वां) और अनमोल इक्का (58वां) ने गोल दागे। वहीं अर्जेंटीना के लिए निकोलस रौद्रिगेज (पांचवां) और सैंटियागो फर्नांडिस (44 वां) ने गोल किए। तीन क्वार्टर तक दो गोल से पिछड़ने के बाद भारत ने शानदार वापसी करते हुए आखिरी क्वार्टर में चार गोल करके खचाखच भरे मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में मानो जान फूंक दी। पहले 49वें मिनट में मिले पेनल्टी कार्नर को अंकित ने गोल में बदलकर भारत का खाता खोला। वहीं 52वें मिनट में भारत को फिर पेनल्टी कार्नर मिला जिस पर अनमोल इक्का के शाट पर गेंद डिफ्लैक्ट होकर मनमीत की स्टिक से टकराकर गोल के भीतर गई। स्कोर 2-2 से बराबर होने के बाद लग रहा था कि मैच शूटआउट में जाएगा लेकिन आखिरी सीटी बजने से तीन मिनट बाकी रहते भारत को अहम पेनल्टी स्ट्रोक मिला जिसे शारदानंद तिवारी ने गोल में बदलकर पहली बार भारत को बढ़त दिलाई।

अर्जेंटीना को अगले मिनट में पेनल्टी कार्नर मिला, लेकिन गोलकीपर प्रिंसदीप सिंह ने एक बार फिर शानदार बचाव किया। भारत को 58वें मिनट में मिले पेनल्टी कार्नर को अनमोल इक्का ने गोल में बदला। भारतीय टीम पहले पूरे क्वार्टर में दबाव में नजर आई। टूर्नामेंट के राउंड राबिन चरण में 29 गोल करने वाली मेजबान टीम कठिन प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ गोल करने के लिए जूझती दिखी।

हाकी

भारत के लिए अंकित पाल (49वां), मनमीत सिंह (52वां), शारदानंद तिवारी (57वां) और अनमोल इक्का (58वां) ने गोल दागे। तीन क्वार्टर तक दो गोल से पिछड़ने के बाद भारत ने शानदार वापसी करते हुए आखिरी क्वार्टर में चार गोल करके खचाखच भरे स्टेडियम में मानो जान फूंक दी।

शूटआउट में स्पेन को हराकर जर्मनी ने आठवीं बार जीता विश्व कप

जर्मनी ने बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में बुधवार को स्पेन को शूटआउट में 3-2 से हराकर आठवीं बार जूनियर पुरुष हाकी विश्व कप जीत लिया। सेमीफाइनल में भारत को हराने वाली जर्मनी के लिए बेनेडिक्ट गेयेर, एलेक वोन श्वेरिन और बेन हासबाश ने गोल किए, जबकि स्पेन के लिए पाब्लो रोमन और जुआन प्राडो ही गोल कर सके। इससे पहले जर्मनी के लिए 26वें मिनट में जस्टस वारवेग ने गोल किया जबकि स्पेन के लिए 54वें मिनट में जी कोरोमिनास ने बराबरी का गोल दागा। जर्मनी सात बार (1982, 1985, 1989, 1993, 2009, 2013, 2023) खिताब जीत चुकी है। वहीं स्पेन ने 2005 और 2023 में कांस्य पदक जीता था।

Source:- दैनिक जागरण

देश में मशरूम उत्पादन में बिहार की 11 प्रतिशत भागीदारी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना : सुपर फूड मशरूम की खेती में दुनिया में भले ही चीन की बादशाहत हो, भारत में तो इसके बाजार में बिहार का राज है। भारत में हो रहे कुल मशरूम के उत्पादन में बिहार का योगदान 11 प्रतिशत पर पहुंच गया है।

मशरूम रिसर्च निदेशालय, सोलन की रिपोर्टों के अनुसार बिहार भारत में मशरूम उत्पादन में नंबर एक पर बना हुआ है। बिहार ने ओडिशा को पीछे छोड़कर यह स्थान हासिल किया है। वर्ष 2010 में बिहार में 400 टन बटन मशरूम एवं 80 टन ओयस्टर मशरूम का उत्पादन होता था। वह बढ़कर आज 41,0310 टन हो गया है। मशरूम की बढ़ती वैश्विक और घरेलू मांग को देखते हुए बिहार सरकार इसकी खेती के लिए सब्सिडी और वित्तीय सहायता दे रही है। एक अनुमान के मुताबिक वैश्विक स्तर पर 2025 तक मशरूम बाजार में $75 बिलियन तक की वृद्धि का अनुमान है। बढ़ती उपभोक्ता मांग और टिकाऊ खेती के तरीकों के कारण मशरूम की खेती एक लाभदायक व्यवसाय बनी रहेगी। इस योजना के तहत किसानों को मशरूम किट और झोपड़ी (मशरूम हट) निर्माण पर 50 से 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। महिला किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है। बिहार में बटन, ओएस्टर और दूधिया मशरूम का उत्पादन होता है। बिहार में 60 से 70 हजार किसान इसकी खेती में लगे हुए हैं। समस्तीपुर में डा. राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय की तरफ से किसानों को मशरूम के विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। किसान पंजीयन करा कर मशरूम की खेती का विधिवत प्रशिक्षण ले सकते हैं।

2010 में 480 टन मशरूम का उत्पादन था, बढ़कर अब हो गया 41,0310 टन

गया मशरूम उत्पादन में अव्वल

जिला उद्यान पदाधिकारी तबस्सुम परवीन ने बताया कि हर घर मशरूम योजना के तरह जिले के लगभग प्रत्येक गांव में चार से पांच परिवार मशरूम उत्पादन से जुड़े हैं। वजीरगंज, कौंच, मानपुर, बोधगया और इमामगंज सहित अन्य क्षेत्रों में मशरूम की खेती हो रही है। गया के मशरूम की मांग दिल्ली, कोलकाता, रांची, जमशेदपुर के बाजारों में भी है।

नौकरी छोड़कर मशरूम की खेती करने लगे कई किसान

गोपालगंज के कुचायकोट के प्रकाश राय विज्ञान स्नातक हैं। कोरोना काल में प्राइवेट नौकरी छोड़कर मशरूम की खेती करने लगे। खेती से पहले उत्पादन व बाजार का आकलन किया। उद्यान विभाग से मशरूम उत्पादन योजना के तहत 30 फीट चौड़ी एवं 50 फीट लंबी झोपड़ी के लिए एक लाख 89 हजार 750 की राशि स्वीकृत हुई थी। इसमें 50 प्रतिशत उद्यान विभाग ने अनुदान दिया था। प्रकाश को मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में उद्यान निदेशालय, पटना की ओर से प्रथम बटन मशरूम पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

वैशाली जिले के हाजीपुर के राजीव रंजन इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद पुणे की एक मल्टीनेशनल कंपनी नौकरी कर रहे थे। दस साल पहले नौकरी छोड़ दी। अब बटन मशरूम की खेती कर रहे हैं। राजीव वैशाली जिले के पहले किसान हैं, जिन्होंने बटन मशरूम की खेती शुरू की। कई सम्मान से सम्मानित राजीव कहते हैं कि जब वह नौकरी के दौरान डेनमार्क गए थे, वहां उन्होंने मशरूम की खेती के बारे में जाना। राजीव अब मशरूम के होलसेलर बन चुके हैं। प्रतिदिन पांच क्विंटल मशरूम की आपूर्ति पटना की मीठापुर मंडी को करते हैं।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी लंबित आवेदनों का निबटारा मार्च तक करें

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना: उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों से कहा है कि आम लोगों से जुड़ी परिमार्जन प्लस एवं दाखिल-खारिज सहित इस विभाग की सभी सेवाएं निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराएं। इसमें किसी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे बुधवार को यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हालांकि उन्होंने दावा किया कि पहले की तुलना में आनलाइन सेवाओं के निष्पादन में काफी सुधार हुआ है। फिर भी सबसे अधिक दाखिल-खारिज में देरी की शिकायतें आ रही हैं। सिन्हा ने कहा कि बिना किसी जरूरी आधार के आवेदनों को निरस्त करने की प्रवृत्ति

उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा

पर तुरंत रोक लगे। उन्होंने बड़ी संख्या में आवेदन रद करने वाले अधिकारियों की जिलावार सूची बनाने का आदेश दिया। सूची के आधार पर पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि फर्जी कागजात पर दाखिल-खारिज करने के लिए दिए गए आवेदनों की जांच के लिए राज्य स्तर पर विशेष टीम का गठन किया जाए। फर्जी दस्तावेज जमा करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो। विशेष टीम मौके पर जाकर जांच करेगी। पीड़ितों का पक्ष भी सुनेगी। सभी सही और वैध लंबित दाखिल-खारिज एवं परिमार्जन प्लस आवेदनों का मार्च तक निष्पादन हो जाएगा।

सभी काम टाइमलाइन में पूरे हों : उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि जनता को भटकने से बचाना है। सभी सही कार्य निर्धारित टाइमलाइन में पूरे हों, यही विभाग की प्राथमिकता है। परिमार्जन प्लस पर आए आवेदनों की निष्पादन दर 27 से 83 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

केंद्र से पूछा, एयरलाइन नाकाम रही तो सरकार ने क्या किया

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा, पांच हजार रुपये का टिकट 35 हजार से 40 हजार रुपये तक कैसे पहुंचे सकता है

इंडिगो संकट

- कोर्ट ने कहा- अन्य एयरलाइंस को किराया बढ़ाने की अनुमति कैसे दी गई?
- यह भी पूछा- क्या डिफाल्ट करने वाली इंडिगो पर कार्रवाई करने में लाचार है सरकार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली सहित देशभर में इंडिगो एयरलाइंस की सैकड़ों उड़ानों के रद होने से हजारों यात्रियों को असहनीय पीड़ा पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कई सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा कि अगर इंडिगो एयरलाइन नियमों का पालन नहीं कर रही थी, तो सरकार ने क्या किया? ऐसी स्थिति में सरकार के पास क्या प्रविधान है और क्या डिफाल्ट करने वाली एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई करने में केंद्र सरकार लाचार है? विमानों के किराये में बेतहाशा बढ़ोतरी पर पीठ ने सवाल किया कि अगर कोई संकट था, तो दूसरी एयरलाइंस को फायदा उठाने की इजाजत कैसे दी गई? पांच हजार का किराया 35 हजार से 40 हजार तक कैसे पहुंच सकता है? दूसरी एयरलाइंस ने बढ़ी दरें वसूलना कैसे शुरू कर दिया?

अदालत ने यह टिप्पणी व सवाल प्रभावित यात्रियों को ग्राउंड सपोर्ट और रिफंड दिलाने की मांग से जुड़ी अधिवक्ता अखिल राणा और उत्कर्ष शर्मा की जनहित याचिका पर किए। हालांकि, पीठ ने बिना किसी शोध और दस्तावेज के याचिका दायर करने पर भी असंतोष व्यक्त किया।

सरकार ने हालात बिगड़ने दिए : पूरे घटनाक्रम को आपात बताते हुए अदालत ने केंद्र सरकार की तरफ से पेश एडिशनल सालिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा से पूछा कि सरकार ने हालात को बिगड़ने दिया

उसके बाद ही कार्रवाई की। सरकार ने यह सब होने क्यों दिया? अदालत ने यह भी कहा कि हम नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हैं, लेकिन हमें इस बात की चिंता है कि ऐसी स्थिति क्यों बनने दी गई, जिससे सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रह गए।

सिर्फ विमान रद होने के लिए नहीं, असुविधा के लिए भी मुआवजा दे इंडिगो : विमान रद व असुविधा होने पर अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में डीजीसीए के कुछ प्रविधानों के तहत मुआवजा देने का नियम है। इंडिगो मुआवजे के भुगतान संबंधी इन प्रविधानों का कड़ाई से पालन करे और इसकी पुष्टि मंत्रालय और डीजीसीए द्वारा भी की जाएगी। यदि कोई अन्य उपाय उपलब्ध हैं, तो प्रतिवादियों द्वारा उनकी पुष्टि सुनिश्चित की जाएगी। अदालत ने इंडिगो से कहा कि वह तुरंत मुआवजा देना शुरू करे। यह भी कहा कि इंडिगो सुनिश्चित करे कि मुआवजा सिर्फ रद होने के लिए देने के बजाय लोगों को हुई असुविधा के लिए भी दिया जाए।

सभी एयरलाइंस में पर्याप्त संख्या में पायलट के लिए उठाएं उचित कदम : अदालत ने कहा कि भारतीय वायुयान अधिनियम- 2024 केंद्र सरकार व डीजीसीए को नियमों का पालन न करने वाली एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है। इसके तहत लाइसेंस या अनुमोदन प्रमाणपत्र को प्रतिबंधित, निलंबित या रद करने का भी अधिकार है।

संबंधित खबरें » पेज 5

दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के कारण पैदा हुई स्थिति : केंद्र

अदालत के सवालों पर केंद्र सरकार और डीजीसीए की तरफ से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने बताया कि दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के कारण ऐसे हालात बने, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस पर उसने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) की योजना वर्ष 2024 से लंबित है और बार-बार इसकी समय-सीमा बढ़ाई गई। मामले में एक कमेटी जांच कर रही है। नियमों के उल्लंघन पर एयरलाइंस पर जुर्माना लगाने के प्रविधान है। सरकार इस पर गौर कर रही है। एएसजी ने अदालत को बताया कि एफडीटीएल के संबंध में इंडिगो को सिर्फ एक बार की छूट दी गई है। यह छूट सिर्फ फरवरी 2026

नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ग्राउंडेड इंडिगो का विमान। • फाइल

तक ही मान्य रहेगी। हर 15 दिन में इसका रिव्यू होगा और हम इसे वापस भी ले सकते हैं। एएसजी ने कहा कि अप्रत्याशित किराया बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले कभी भी किराये की अधिकतम सीमा तय नहीं की गई थी।

केंद्र सरकार से अदालत के तीखे सवाल

- एयरपोर्ट पर प्रभावित हुए यात्रियों की मदद के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए
- यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई कि एयरलाइंस कर्मचारी उनके साथ ठीक से व्यवहार करें
- सरकार ने पायलटों के काम के घंटों पर दिशानिर्देश को समय पर लागू क्यों नहीं किया?
- क्या एफडीटीएल को लागू न करने से यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा?
- अगर किसी पायलट को एक रात में दो लैंडिंग करनी हैं और वह छह कर रहा है, तो क्या वह लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं कर रहा है?
- एयरलाइंस द्वारा पर्याप्त संख्या में पायलटों की भर्ती न करने पर क्या कार्रवाई की गई?

विश्व विरासत बनकर दुनिया में रोशनी बिखेरेगी दीपावली, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित

लाल किला में बुधवार को यूनेस्को की अंतर-सरकारी समिति की बैठक के दौरान दीपावली को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने की घोषणा के बाद प्रसन्न मुद्रा में केंद्रीय स मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (आगे मध्य) व अन्य। ● आइएएनएस

उपलब्धि

- लाल किले में आयोजित बैठक में यूनेस्को ने की घोषणा, पहले से 15 धरोहरें हैं शामिल
- गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत और दुनियाभर के लिए इसे अत्यंत गौरव का क्षण बताया

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : प्रकाश पर्व दीपावली अब विश्व विरासत बनकर दुनिया में अपनी रोशनी बिखेरेगी। यूनेस्को ने दीपावली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया है। यह फैसला बुधवार को दिल्ली के लाल किले में आयोजित यूनेस्को की अंतर-सरकारी समिति की बैठक में लिया गया। लाल किला खुद भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। जैसे ही यूनेस्को ने दीपावली को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने की घोषणा की, वंदे मातरम् और भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। इस दौरान पारंपरिक परिधानों में सजे कलाकारों ने मुख्य मंच के सामने प्रस्तुतियां दीं, जबकि बड़ी स्क्रीन पर दीपावली के दृश्य प्रदर्शित किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भारतीय दल के अन्य सदस्यों ने इस अवसर पर पारंपरिक पगड़ी पहन रखी थी।

जागरण ब्यूरो के अनुसार, यह पहला मौका है जब भारत यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए अंतर-सरकारी समिति के सत्र की मेजबानी कर रहा है। समिति का 20वां सत्र आठ से 13 दिसंबर तक लाल किले में चल रहा है। दीपावली को 194 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विश्व विरासत घोषित किया गया। प्रेट्र के अनुसार, पाकिस्तान ने दीपावली को विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने का स्वागत किया है। नई दिल्ली स्थित उच्चायोग में तैनात पाकिस्तानी राजनयिक शोएब सरवर संधू ने कहा- दीपावली को अमूर्त विरासत सूची में शामिल किए जाने पर भारत को मेरी बधाई। एक दिन पहले पाकिस्तान के लुप्तप्राय लोक संगीत वाद्ययंत्र बोरींदो, पैराग्वे का सिरेमिक शिल्प कौशल और केन्या के मवाजिंदिका नृत्य सहित 11 धरोहरों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था।

हर देश दो वर्ष में एक धरोहर को नामांकित कर सकता है। भारत ने 2024-25 चक्र के लिए 2023 में दीपावली का नामांकन किया था।

> भारत और दुनियाभर के लोग रोमांचित हैं। हमारे लिए दीपावली हमारी संस्कृति और लोकाचार से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। यह हमारी सभ्यता का आत्मा है। यह प्रकाश और धार्मिकता का प्रतीक है। यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में दीपावली के शामिल होने से इस त्योहार की वैश्विक लोकप्रियता और भी बढ़ जाएगी। प्रभु श्रीराम के आदर्श शाश्वत रूप से हमारा मार्गदर्शन करते रहें।
>
> -नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

> यह भारत के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है, क्योंकि दीपावली यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल हो गई है। यह आधुनिक युग में भी हमारी प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं के महत्व को दर्शाता है। प्रकाश का यह पर्व प्राचीन काल से ही हमें अच्छाई और धर्म की जीत में विश्वास करने के लिए प्रेरित करता रहा है। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि अब यह वैश्विक कल्याण को बढ़ावा देगा।
>
> -अमित शाह, गृह मंत्री

यूनेस्को की सूची में भारत

यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भारत की 15 धरोहरें हैं। इनमें कुंभ मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा नृत्य, योग, वेद पाठ, रामलीला, केरल की नाट्यशैली कुटियाट्टम, गढ़वाल का त्योहार रम्माण, लोक कलाओं पर आधारित छाऊ नृत्य, राजस्थान का नृत्य कालबेलिया, केरल का नृत्य नाटक मुडियेट्टू, लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, मणिपुर का नृत्य संकीर्तन, पंजाब में ठठेरों द्वारा पीतल और तांबे की कारीगरी और पारसी त्योहार नवरोज शामिल हैं।

बिहार के पांच जिलों में 70,000 टन क्षमता का बन रहा गोदाम

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा में डा. भीम सिंह के पूरक प्रश्न पर सदन को दी जानकारी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना : सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बुधवार को राज्यसभा में डा. भीम सिंह के पूरक प्रश्न पर सदन को बताया कि केंद्र सरकार 70,000 टन की भंडारण क्षमता का अनाज गोदाम विकसित करने की कार्य योजना पर काम कर रही है। वर्तमान में बिहार से नालंदा, नवादा, जहानाबाद, लखीसराय, गया सहित पांच जिलों के 22 स्थानों पर कुल 24,000 टन क्षमता के भंडारण निर्माण हेतु डीपीआर प्राप्त हो चुके हैं। इनमें नालंदा जिले में दो स्थानों पर लगभग 10,000 टन क्षमता वाले गोदाम का कार्य प्रारंभ भी हो चुका है तथा अन्य प्रस्ताव प्रक्रियागत स्थिति में हैं। मंत्री ने कहा कि यह योजना सहकारिता तंत्र को मजबूत करने, पैक्स स्तर पर भंडारण क्षमता बढ़ाने और किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्र सरकार विशेष रूप से उन राज्यों के साथ निरंतर समन्वय कर रही है, जहां प्रगति तुलनात्मक रूप से धीमी है। ताकि, योजना का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

जिला स्वास्थ्य सूचना प्रणाली में प्रदेश सबसे आगे

1.65 करोड़ से अधिक डिजिटल ओपीडी रजिस्ट्रेशन हुए छह माह में

कम आय वाले देशों में हेल्थ आइटी उपयोग के लिए कई देशों के 150 से ज्यादा विशेषज्ञों का हुआ जुटान

आद्री का स्वास्थ्य सूचना प्रौद्योगिकी के नवाचारों पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन शुरू

सीआइएमपी में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद अतिथि ● जागरण

जागरण संवाददाता, पटना : प्रदेश की जनसंख्या बहुत बड़ी नहीं होने के बावजूद स्कैन एंड शेयर यानी अस्पतालों की ओपीडी में डिजिटल टोकन आधारित पंजीकरण में देश में शीर्ष पर है। इसके अलावा प्रदेश जिला स्वास्थ्य सूचना प्रणाली पंजीकरण में भी सबसे आगे है और इलेक्ट्रानिक हेल्थ रिकार्ड (ईएचआर) में तीसरे, आभा में चौथे स्थान पर है। कुल मिलाकर प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र के डिजिटलीकरण में अग्रणी है। यह जानकारी बुधवार को बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के सीईओ शशांक शेखर सिन्हा ने दीं। वे कम व मध्यम आय वाले देशों में स्वास्थ्य सूचना प्रौद्योगिकी के नवाचारों पर शुरू दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टिट्यूट (एडीआरआइ) का सेंटर फार हेल्थ पालिसी (सीएचपी) कर रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य यह समझना है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी किस प्रकार स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान कर निर्णय प्रक्रिया को सशक्त बना सकती है। सम्मेलन में देश-विदेश के 150 स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भाग लिया।

उद्घाटन सत्र में वरिष्ठ पत्रकार सह पूर्व राष्ट्रपति के प्रेस सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि आद्री बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने में अग्रणी है।

स्कैन एंड शेयर, बिना कतार सटीक जानकारी

स्कैन एंड शेयर अस्पतालों में मरीजों के तेज़, बिना कागज वाले ओपीडी पंजीयन की सुविधा देता है। इसमें अस्पताल में लगे क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करने पर आभा स्वास्थ्य पहचान से सटीक बुनियादी जानकारी अपने-आप अस्पताल के सिस्टम में साझा हो जाती है। मरीज को काउंटर पर दोबारा फार्म भरने या लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती और मरीज को पंजीयन तुरंत हो जाता है।

डीएचआइएस से जिले में किस रोग का प्रकोप तुरंत हासिल की जा सकती है जानकारी

जिला स्वास्थ्य सूचना प्रणाली (डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफार्मेशन सिस्टम) जिले से लेकर राज्य व दिल्ली तक स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों को आनलाइन एकत्र, अपडेट व विश्लेषित करने का मंच है। इसमें भर्ती, जांच व इलाज संबंधी आंकड़े, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, रोगों के फैलाव से जुड़ी जानकारी व स्वास्थ्य योजनाओं के आंकड़े अपलोड किए जाते हैं।

उद्योग के लिए राज्य में 50 लाख करोड़ का होगा निवेश : दिलीप

जागरण संवाददाता, पूर्णिया: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व उद्योग मंत्री डा. दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्य में 25 चीनी मिल स्थापित करने का लक्ष्य है। जिस क्षेत्र में गन्ना की पैदावार होती है उस क्षेत्र को प्राथमिकता में रखा गया है। राज्य में सेमी कंडेक्टर प्लांट लगाने का प्रयास किया जा रहा है। औद्योगिक विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना है, जिससे उद्योग की स्थापना होगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा।

उन्होंने कहा कि केवल बड़े उद्योगों पर ही फोकस नहीं किया जा रहा है बल्कि घर-घर उद्योग और हर हाथ को काम देने के सपने को साकार किया जाएगा। इसके लिए सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों की स्थापना पर भी बल दिया जा रहा है। स्वदेशी और घरेलू उद्योग को सरकार की तरफ से मदद की जाएगी। कहा, जनता ने फिर से एनडीए को राज्य की बागडोर सौंपी

प्रेस वार्ता करते उद्योग मंत्री डा. दिलीप जायसवाल ■ जागरण

है। एनडीए की सरकार विकसित बिहार बनाने के लिए संकल्पित है। अपराध मुक्त बिहार, रोजगार युक्त बिहार इसी सपने के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस चुनाव में विपक्षी दलों ने जो भ्रम जाल फैलाया था उसके बावजूद इस तरह का बहुमत मिला और जनता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और गारंटी पर भरोसा किया है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं का हृदय से आभार है। कानून का राज्य स्थापित किया जाएगा। राज्य को अपराध मुक्त बनाया जाएगा।

उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टार्टअप इकोसिस्टम की तैयारी

हर विश्वविद्यालय में स्टार्टअप सेल की होगी स्थापना, उच्च शिक्षण संस्थानों में उद्यम के इच्छुक छात्रों को किया जाएगा तैयार

दीनानाथ साहनी • जागरण

पटना : बिहार में औद्योगिकीकरण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही राज्य सरकार सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने में जुटी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर शिक्षा विभाग और उद्योग विभाग मिलकर स्टार्टअप इकोसिस्टम के माध्यम से युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करेंगे। जल्द ही सभी विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में स्टार्टअप सेल को भी स्थापित करने की तैयारी हो रही है। राज्य के उद्योग मंत्री डा. दिलीप कुमार जायसवाल के मुताबिक स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्टेप वाइज आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। इसके लिए विश्वविद्यालयों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुदृढ़ किया जाएगा। बिहार में उद्योग लगाने वाले उद्यमी युवाओं को सुरक्षा सहित सभी आवश्यक सुविधाएं राज्य सरकार मुहैया कराएगी।

- शिक्षा विभाग और उद्योग विभाग संयुक्त रूप से विकसित करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर
- छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के साथ-साथ कमाई का गुर भी सिखाया जाएगा

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड से 20 लाख अनुदान की सुविधा

शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पढ़े-लिखे युवा रोजगार करेंगे तो केंद्र सरकार से भी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड से 20 लाख रुपये के अनुदान की सुविधा दी जाती है। लेकिन, युवाओं को रोजगार करने संबंधी स्किल विकसित करनी होगी। इसीलिए उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं के लिए इनक्यूबेशन सेंटर को बढ़ावा देने हेतु बुनियादी ढांचे और मार्गदर्शन की सुविधा देने जा रही है।

पढ़ाई के साथ-साथ कमाई के गुर भी सीखेंगे युवा : शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाल में राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार को प्राथमिकता देने को कहा है। इसके मद्देनजर अब छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के साथ-साथ कमाई का गुर भी सिखाया जाएगा। प्रत्येक विश्वविद्यालय में स्टार्टअप को स्टेप वाइज आगे बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसपर उद्योग विभाग के साथ मिलकर स्टार्टअप इकोसिस्टम को तैयार करने पर कार्ययोजना बनायी जाएगी, ताकि युवाओं को नौकरी खोजने वालों से नौकरी देने वाला बनाया जा सके। उन्हें उद्यमिता के लिए प्रेरित किया जा सके, कौशल विकास और इनक्यूबेशन सहायता दी जा सके और उन्हें सफल उद्यम स्थापित करने के लिए एक इकोसिस्टम प्रदान किया जा सके। यही व्यवस्था सभी राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पालीटेक्निक संस्थानों में की जाएगी।

मैनेजमेंट और मार्केटिंग की ट्रेनिंग की सुविधा भी

पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र-छात्राओं को रोजगार करने एवं उद्यमी बनने के लिए स्किल डेवलपमेंट, मैनेजमेंट और मार्केटिंग की ट्रेनिंग की सुविधा भी दी जाएगी। उद्यम खड़ा करने के लिए शुरुआत में पूंजी की व्यवस्था कराई जाएगी। उनकी पहुंच निवेशकों तक बढ़ाई जाएगी। नेटवर्किंग बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि उच्च शिक्षा पाने वाले छात्र सिर्फ नौकरी खोजने के बजाय खुद नौकरी बनाने वाले (जाब क्रियेटर्स) बनें।

हर छात्र को मिलेगा मेंटरशिप और इनक्यूबेशन सपोर्ट

प्रस्ताव के मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने वाले हर छात्र-छात्रा को बीज निधि (सीड फंडिंग), मेंटरशिप और इनक्यूबेशन सपोर्ट देकर उद्यमी बनने में मदद दी जाएगी। ऐसे युवाओं को नवाचार, रोजगार सृजन, व्यावहारिक कौशल, वित्तीय सहायता और उद्यमशीलता की मानसिकता के माध्यम से कई लाभ प्रदान किए जाएंगे, जिससे वे नौकरी चाहने वालों से नौकरी देने वाले बन सकें। यहां इनक्यूबेशन सपोर्ट का उद्देश्य है स्टार्टअप और नए व्यवसायों को शुरुआती चरण में विकसित होने और सफल होने के लिए दी जाने वाली मदद। जिसमें मार्गदर्शन, आफिस स्पेस, फंड (पूंजी), नेटवर्क और तकनीकी सहायता शामिल है।

पांच वर्षों में संवरी करीब 38 हजार कुओं की सूरत

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : जल जीवन हरियाली मिशन ने पिछले साढ़े पांच वर्षों में जल स्रोतों को बचाने की दिशा में ऐसा काम किया है, जिसकी मिसाल वर्षों तक दी जाएगी। भूगर्भ जलस्तर बढ़ाने एवं परंपरागत जल संसाधनों को संवारने के लिए चिह्नित 38 हजार 629 कुओं में से 37 हजार 995 कुओं का जीर्णोद्धार पूरा हो चुका है। शेष 293 कुओं पर काम जारी है।

सरकार ने ग्रामीण विकास समेत कई विभागों के सहयोग से यह अभियान 25 सितंबर 2019 को शुरू किया था। मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद योजना ने गति पकड़ी और कुओं से अतिक्रमण हटाने से लेकर उनके संरक्षण तक का पूरा खाका तैयार किया गया। इसी दौरान योजना का बजट भी बीते वर्षों में करीब नौ गुना बढ़ाया गया। पहले निर्धारित राशि एक हजार 359 करोड़ से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2024-25 में 12 हजार 568 करोड़ रुपये कर दी गई। बढ़े हुए संसाधनों का परिणाम है कि आज लगभग सभी चिन्हित कुओं का कायाकल्प पूरा होने की कगार पर है।

> पारंपरिक जलस्रोतों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने और भूगर्भ जलस्तर को बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम जारी है। कई कार्य पूरे हो चुके हैं। कुछ काम शेष है जिन्हें शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा।
> -श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री

अतिक्रमण हटाने की सबसे बड़ी मुहिम : राज्यभर में चिह्नित 11 हजार 192 सरकारी कुओं में से 11 हजार 181 को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। बाकी 11 कुओं पर प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में 17 हजार 454 तालाब, पोखर, आहर, पईन और अन्य जल स्रोतों से अवैध कब्जा हटाकर उनका जीर्णोद्धार भी पूरा किया जा चुका है।

वर्ष 2019 में मिशन की शुरुआत के बाद पहली बार पूरे राज्य में उपेक्षित जल स्रोतों की व्यापक पहचान हुई। वर्षों से कब्जे और अव्यवस्था की मार झेल रहे ये पौराणिक संसाधन आज फिर से जीवनदान देने की स्थिति में हैं।

ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जहां वर्षों पुराना अतिक्रमण हटाना चुनौती था, वहां मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना कारगर सिद्ध हुई है। जिन लोगों के पास रहने के लिए अपनी जमीन नहीं है, उन्हें इस योजना के तहत एक लाख रुपये की सहायता प्रदान कर वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि जल स्रोतों को मुक्त कर उनका संरक्षण किया जा सके। नतीजे साफ हैं कि बिहार की धरती पर पानी का भविष्य फिर से सुरक्षित दिखने लगा है।

अराजकता को आमंत्रण देने वाली व्यवस्था

तरुण गुप्त

इंडिगो प्रकरण से यही प्रकट हुआ कि सुविधाओं की बात तो बहुत दूर है, भारतीय विमान यात्री मूलभूत उपभोक्ता अधिकारों के लिए भी जूझते हैं

बीते दिनों भारतीय हवाई अड्डों पर भारी अराजकता दिखी। इस स्थिति को कैसे अभिव्यक्त किया जाए? परिदृश्य निर्धारण की प्रक्रिया में ऐसे असामान्य घटनाक्रम को विश्लेषक प्रायः ब्लैक स्वान और ग्रे स्वान जैसी संकल्पनाओं से निर्धारित करते हैं। इनमें ब्लैक स्वान एक अप्रत्याशित, अनपेक्षित एवं अनजानी घटना होती है। इसके गंभीर और प्रतिकूल परिणाम निकलते हैं। क्या इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद होने को इस श्रेणी में रखा जा सकता है? इसकी पड़ताल करें तो पायलटों के लिए अधिक विश्राम एवं संशोधित रोस्टर के सरकारी नियम दो साल पहले ही बन गए थे। विमानन कंपनियों को इसके पालन की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया गया। इसमें कुछ भी अप्रत्याशित एवं अनिश्चित नहीं था। स्वाभाविक है कि अनुपालन के अभाव में अव्यवस्था उपजनी ही थी और ऐसा ही हुआ भी।

ग्रे स्वान घटनाक्रम का यह आशय होता है कि किसी घटना की भविष्यवाणी के बावजूद वह असंभावित होती है। ऐसी घटना का भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इंडिगो प्रबंधन संभवतः इसी भ्रम में रहा कि सख्त दिशानिर्देश दिखावटी पहल हैं, जिन पर शायद ही अमल हो। संशोधित नियमों को लेकर लंबे समय तक शिथिलता, अनुपालन की सीमा बढ़ाते रहने के बावजूद क्या यह वाकई इतना अप्रत्याशित था कि कभी तो प्राधिकारी संस्था विमानन सुरक्षा और बेहतर कार्यसंस्कृति की दिशा में अग्रसर होगी?

ब्लैक और ग्रे स्वान को लेकर ऊहापोह के बीच मुझे रेड स्वान अधिक उपयुक्त लगा। यह ऐसे परिदृश्य का संकेत करता है, जिसकी संभावना काफी अधिक होती है। अक्सर चर्चा के साथ उसकी चेतावनी भी दी जाती है। इसके बावजूद जिम्मेदार लोगों की निष्क्रियता के कारण प्रतिकूल परिणामों का सामना करना पड़ता है। डीजीसीए ने संशोधित उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) की घोषणा करीब दो वर्ष पहले कर दी थी। इंडिगो इससे भलीभांति अवगत भी थी। फिर भी, उसने इसे अनदेखा करना ही उचित समझा जो नितांत अनुचित था। स्पष्ट है कि वह नए नियमों से पड़ने वाले वित्तीय बोझ से बचना चाहती थी। यह कुछ और नहीं, बल्कि बाजार की अग्रणी कंपनी की मनमानी का उदाहरण है। अव्यवस्था के बाद से ही इस प्रकरण से जुड़े विभिन्न पक्ष सफाई देने में लगे हैं। सरकार ने फिलहाल संशोधित नियम कुछ समय के लिए टालते हुए किराये की सीमा तय कर दी है। इंडिगो ने क्षमायाचना करते हुए बुकिंग धनराशि वापस करने की घोषणा की है। भले ही कुछ दिनों में इस संकट से थोड़ी राहत मिल जाए, लेकिन यक्ष प्रश्न यही है कि क्या यह राहत स्थायी होगी?

अवधेश राजपूत

साल का सिंहावलोकन करें तो भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए यह वर्ष काफी खराब रहा। जून में एअर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। कुछ हेलीकाप्टर भी दुर्घटना के शिकार बने और अब इंडिगो विमानों के बेड़े पस्त पड़े। अंततः इसकी तपिश उपभोक्ताओं को ही झेलनी पड़ती है। यह आगे कुआं-पीछे खाई वाली कहानी है। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के बीच द्वंद्व की स्थिति है। यह बहस की बात ही नहीं है कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता हो अथवा पायलटों को विश्राम देने वाले नियमों में कोई ढिलाई दी जाए। काकपिट में काम के बोझ तले दबे और पर्याप्त विश्राम से वंचित पायलट कतई नहीं होने चाहिए, लेकिन क्या ऐसी व्यापक सुरक्षा की कीमत बड़े पैमाने पर उड़ानों के रद होने और अराजकता को आमंत्रण देकर ही चुकाई जाएगी?

निःसंदेह सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन हमें उससे आगे भी जाना होगा। जैसे यात्रियों की सहूलियतों और अनुभव का स्तर। सेवा क्षेत्र का हिस्सा होने के साथ विमानन आतिथ्य सेवा का ही विस्तार माना जाता है। हालांकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है। सुविधाओं की बात छोड़िए, यहां तो यात्री मूलभूत उपभोक्ता अधिकारों के लिए ही जूझते हैं। भारत में यात्रियों के अधिकार से जुड़े दस्तावेज बेमानी ही हैं। उन पर कभी-कभार ही कोई कार्रवाई होती है। होती भी है तो केवल खानपान और रिफंड जैसे मुद्दों तक ही सीमित होकर रह जाती है। विकसित देशों के उलट भारत में विमानन कंपनी को परिचालन अक्षमता के लिए दंडित नहीं किया जाता।

आप भले ही कम दरों वाले टिकट अग्रिम रूप से बुक करके रखें, किंतु निर्धारित उड़ान विलंबित या रद होने की स्थिति में वैकल्पिक टिकट खरीदने के लिए बाध्य यात्री को मूल टिकट से मिलने वाले रिफंड से कहीं अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। एयरलाइन बिना किसी पूर्व सूचना के उड़ान में देरी और उसे रद तक कर सकती है, लेकिन यात्री का जरा भी विलंब से आना अस्वीकार्य है। परिचालन के स्तर पर यह एक अनिवार्यता हो सकती है, लेकिन स्पष्ट रूप से एकतरफा है। नियमों में इतना संशोधन तो आवश्यक है कि एयरलाइन को उसकी गलती के कारण विलंबित या रद होने वाली उड़ान के एवज में यात्रियों को पर्याप्त मुआवजा देना अनिवार्य हो। यूरोप और अमेरिका में यह एक सामान्य चलन है।

इंडिगो पर कठोर कार्रवाई की घोषणा, उसकी उड़ानों की संख्या में कटौती और सुरक्षा मानकों पर कोई समझौता न करने की सरकार की पहल सराहनीय है। बाजार की अगुआ कंपनी के पर कतरने के इस प्रयास में भले ही समाजवादी दौर के ध्वंसावशेष प्रतीत होने का जोखिम दिखता हो, किंतु वर्तमान स्थिति में यह मुख्य मुद्दे को विस्मृत करने जैसा होगा। राज्य की यह कार्रवाई किसी कंपनी पर प्रहार के बजाय अनुपालन सुनिश्चित करने के तौर पर देखी जानी चाहिए। वैसे भी आवश्यक सेवाओं में किसी भी तरह का एकाधिकार पूर्णतः अस्वीकार्य होना चाहिए। पूंजीवाद और मुक्त बाजार के गढ़ माने जाने वाले अमेरिका में भी अहम सेवाओं में एकाधिकार से निपटने के प्रति सतर्कता का भाव रहा है।

दो कंपनियों का वर्चस्व मुक्त बाजार की अच्छी सेहत का संकेत नहीं कहा जा सकता। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार और चौथी सबसे बड़ी आर्थिकी है, लेकिन यहां की दो एयरलाइंस-इंडिगो (65 प्रतिशत) और एअर इंडिया (30 प्रतिशत) ही 95 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ लगभग पूरे बाजार पर कब्जा किए हुए हैं। हमें बाजार में कुछ और एयरलाइंस के साथ ही सार्थक नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। भारतीय बाजार तेजी से विस्तार कर रहा है और विमानन संबंधी बुनियादी ढांचे को भी इस तेजी से ताल मिलानी होगी। यात्रियों की सुरक्षा और संतुष्टि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के मूल में होनी चाहिए।

response@jagran.com

एडीबी ने भारत का विकास दर अनुमान बढ़ाया

6.5% की बजाय 7.2% किया, कहा-भारत की वजह से दक्षिण एशिया की विकास दर बेहतर रहेगी

- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने सरकार की तरफ से उठाए गए सुधारवादी कदमों को सराहा
- महंगाई दर में आएगी गिरावट एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिकी का दर्जा बरकरार रखा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच और आरबीआइ के बाद अब एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भी चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमान को संशोधित किया है। सितंबर, 2025 में एडीबी ने भारत की सालाना आर्थिक विकास दर के 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया है। भारत में महंगाई दर में और गिरावट का अनुमान भी एडीबी ने लगाया है। एडीबी ने दक्षिण एशिया की विकास दर को ऊपर की तरफ संशोधित किया है और इसके लिए भारतीय इकोनमी के शानदार प्रदर्शन को प्रमुख कारण बताया है। एडीबी ने दक्षिण एशिया के विकास दर अनुमान को 5.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है।

एडीबी ने बुधवार को 'एशियन डेवलपमेंट आउटलुक' (अप्रैल 2025 अपडेट) रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारतीय इकोनमी को लेकर काफी सकारात्मक टिप्पणियां की गई हैं और हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए सुधारवादी कदमों की भी तारीफ की है। एडीबी ने कहा है कि विकास अनुमान में संशोधन के साथ भारत एक बार फिर एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इसके लिए बैंक ने भारत की मजबूत घरेलू मांग, सरकारी पूंजीगत व्यय में निरंतरता और विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन को बड़ा कारण बताया है। एडीबी की उक्त रिपोर्ट के मुताबिक, 'इस संशोधन का मुख्य कारण वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपेक्षा से कहीं बेहतर 8.2 प्रतिशत की वृद्धि रही। इसकी वजह से वित्त वर्ष की पहली छमाही में विकास दर आठ प्रतिशत रही है। यह मजबूत प्रदर्शन घरेलू मांग में सुधार होने के साथ ही मैन्यूफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र के जोरदार विस्तार से संभव हुआ।

अमेरिकी टैरिफ से निर्यात में आ सकती हैं कुछ और अड़चनें

उपभोग और निवेश में सुधार होने का असर दिखने लगा है। निर्यात की स्थिति भी ठीक है, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ बढ़ने से पहले एडवांस में जो आर्डर लिए गए थे वह मजबूत थे और भारतीय उत्पादों का गैर-अमेरिकी बाजारों में विविधीकरण किया गया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दूसरी छमाही में ग्रोथ रेट के सुस्त पड़ने की संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार राजकोषीय समायोजन के लिए पूंजीगत व्यय को नियंत्रित कर रही है। ऊंचे अमेरिकी टैरिफ के कारण कुछ सेक्टर में निर्यात के प्रभावित होने की संभावना है जिससे निर्यात में कुछ अड़चनें आ सकती हैं।

बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में और गिरावट आने की संभावना

रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए सालाना आर्थिक विकास दर अनुमान को बेहतर किया गया है। अब पाकिस्तान की इकोनमी 2.7 प्रतिशत के बजाए तीन प्रतिशत की विकास दर हासिल कर सकती है। हालांकि, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में और कमजोरी आने की संभावना है। बांग्लादेश के आंतरिक हालात व राजनीतिक अस्थिरता को एक बड़ा कारण बताया गया है।

काशी विश्वनाथ कारिडोर की तर्ज पर विकसित होगा हरिहरनाथ

संसू, जागरण, नयागांव (सारण) : लोक परंपरा, व्यापार और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का बुधवार की शाम राजकीय तौर पर समापन हो गया। राज्य के पर्यटन, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर मेले के समापन की औपचारिक घोषणा की। घोषणा की कि हरिहरनाथ कारिडोर को काशी विश्वनाथ कारिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केवल मेला नहीं, बल्कि बिहार की सांस्कृतिक आत्मा है। सदियों से यह मेला लोगों को जोड़ने, परंपराओं को आगे बढ़ाने और व्यापार को नई दिशा देने का काम करता आया है। राज्य सरकार की कोशिश है कि आने वाले वर्षों में सोनपुर मेले को अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग मेले के ढांचे को आधुनिक सुविधाओं से लैस करेगा, ताकि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों का अनुभव और बेहतर हो। हम इस मेले को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने के लिए डिजिटल प्रमोशन, सांस्कृतिक एक्सचेंज कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय कलाकारों की भागीदारी जैसे नए कदमों पर काम कर रहे हैं।

उप विकास आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल को प्रमाण पत्र देते पर्यटन सह कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद। ● जागरण

सोनपुर विधायक विनय कुमार सिंह ने सोनपुर मेले के दौरान बेहतर विधि व्यवस्था को लेकर डीएम व एसपी को साधुवाद दिया। कार्यक्रम में छपरा सदर की विधायक छोटी कुमारी, सोनपुर नगर परिषद सभापति अजय कुमार शाह, उप सभापति अंजली कुमारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। मेले के आखिरी दिन भी मुख्य पंडाल और विभिन्न प्रदर्शनी परिसर में भारी भीड़ उमड़ी रही। सांस्कृतिक मंडपों में लोक नृत्य और वादन कार्यक्रमों ने लोगों को देर शाम तक बांधे रखा। व्यापारियों ने बताया कि गत वर्ष की तुलना में इस बार भीड़ अधिक रही और बिक्री उत्साहजनक रही। कई दुकानदारों ने कहा कि सोनपुर मेला उनकी सालभर की आर्थिक गतिविधियों को संबल देता है। भले ही सरकार ने समापन की घोषणा कर दी हो, परंतु मेले की रौनक और चहलपहल अभी भी बरकरार है। स्थानीय युवाओं से लेकर दूरदराज से आए पर्यटक तक आखिरी पलों का आनंद लेते दिखे। इस प्रकार परंपरा और आधुनिकता का संगम माना जाने वाला सोनपुर मेला एक बार फिर यादों, रोशनी और उत्साह के साथ अगले वर्ष की प्रतीक्षा में विदा हो गया।

राजगीर खेल अकादमी को एशियन हाकी फेडरेशन अकादमी व हाकी सेंटर आफ एक्सीलेंस की मान्यता

जागरण संवाददाता, पटना: राज्य खेल अकादमी राजगीर को एशियन हाकी फेडरेशन अकादमी और हाकी सेंटर आफ एक्सीलेंस की मान्यता मिल गई है। प्रमाणपत्र अंतरराष्ट्रीय हाकी फेडरेशन (एफआइएच) के अध्यक्ष द्वारा बुधवार को चेन्नई में आयोजित जूनियर वर्ल्ड कप हाकी के फाइनल मैच के बाद आयोजित विशेष समारोह में अंतरराष्ट्रीय हाकी फेडरेशन के अध्यक्ष तैयब इकराम द्वारा हाकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवींद्रण शंकरण की उपस्थिति में बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह को सौंपा गया। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि देश के राष्ट्रीय खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा राज्य खेल अकादमी को मिली यह मान्यता न केवल बिहार के लिए गर्व की बात है, बल्कि बिहार की उभरती खेल शक्ति का प्रमाण और एशियाई हाकी की संरचना में बिहार की मजबूत उपस्थिति को भी रेखांकित करती है।

कार्यक्रम में उपस्थित (बाएं से) बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवींद्रण शंकरण, खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, अंतरराष्ट्रीय हाकी फेडरेशन के अध्यक्ष तैयब इकराम और हाकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह● सौ: खेल प्राधिकरण

एशियन हाकी फेडरेशन की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी को एशियन हाकी फेडरेशन अकादमी और हाकी सेंटर आफ एक्सीलेंस के रूप में प्रमाणित करते हुए हमें खुशी हो रही है। यह मान्यता अकादमी के विजन, विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना, जमीनी स्तर से लेकर हाई परफार्मेंस सेंटर तक हाकी के विकास के लिए संस्थागत तैयारी और समर्पण को दर्शाती है। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवीन्द्रण शंकरण ने इस उपलब्धि को गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि यह सफलता बिहार में अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं, निरंतर निवेश और सरकार की सकारात्मक खेल नीति और सहयोग का प्रतिफल है।